



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28082024-256701  
CG-MH-E-28082024-256701

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668]  
No. 668]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
(मानव संसाधन विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 28 अगस्त, 2024

क्रमांक- यूबीआई/एचआर/16061(ई).—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, एतद्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा.  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (बाद में उक्त विनियम के रूप में संदर्भित) के, विनियम 2 में, खंड (एस) में, उप-खंड (डी) में, निम्नलिखित प्रावधान प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :-

"बशर्ते कि 1 नवंबर, 2012 से शुरू किए गए विशेष भत्ते को अपवर्जित रखा जाएगा:

बशर्ते कि कोई कर्मचारी जो 1 नवंबर, 2017 को बैंक की सेवा में था और जिसकी गतिरोध वेतन वृद्धि को उनके अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने की तिथि से संशोधित आवधिकता के अनुसार पुनःसमायोजित किया गया है, वे इस तरह के संशोधित गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए 1 नवंबर, 2017 से पेंशन के प्रयोजनों के लिए कल्पित रूप में पात्र होंगे, लेकिन इस तरह के पुनः समायोजन के कारण आर्थिक लाभ केवल 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान प्रविष्ट किए गए हैं अर्थात्:-

"बशर्ते कि किसी कर्मचारी को हटाया गया है, जो बैंक की सेवा में स्केल वेतन पर स्थायी आधार पर पूर्णकालिक कामगार या स्थायी आधार पर अंशकालिक कामगार के रूप में कार्यरत है, उसकी पिछली पूरी सेवा को समपहत नहीं किया जाएगा और वह पेंशन लाभ के लिए पात्र होगा"

4. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खंड (एफ) के बाद, निम्नलिखित खंड प्रविष्ट किए जाएंगे अर्थात्: -

"(जी) अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर, किसी कर्मचारी के संबंध में प्रति माह तीन हजार नौ सौ पचासी रुपये, जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2017 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ है, अंशकालिक कर्मचारी जो 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं 1/3 वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में एक हजार तीन सौ पैंतीस रुपये, 1/2 स्केल वेतन के अंशकालिक कर्मचारी संबंध में दो हजार रुपये प्रति माह, और 3/4 स्केल वेतन प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में तीन हजार रुपये प्रति माह।

5. उक्त विनियमों के विनियम 40 में,

(ए) उप विनियम (1) में,

(i) खंड (बी) में, प्रथम प्रावधान के लिए, निम्नलिखित प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि बेटे या बेटी (विधवा या तलाकशुदा सहित) को देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी जब पात्र बेटा या बेटी सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार या स्व रोजगार से बारह हजार रुपये प्रति माह से अधिक की राशि अर्जित करना शुरू कर देता है:"

(ii) खंड (सी) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(सी) माता-पिता के मामले में, पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी यदि सरकारी या निजी क्षेत्र या स्व-रोज़गार से माता-पिता में से किसी एक की आय या दोनों की कुल आय रुपये बारह हजार प्रति माह से अधिक हो जाती है";

(बी) उप-विनियम (4) में,-

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: --

"(vii) छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये प्रति माह केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों और कामगार दोनों के संबंध में, जो नवंबर, 2017 के पहले दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या निधन हुआ:

बशर्ते कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन से, उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपरोक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 का उप-विनियम (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी";

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: --

"(vii) छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये प्रति माह केवल उन कर्मचारियों, दोनों अधिकारियों और कामगार दोनों के संबंध में, जो नवंबर, 2017 के पहले दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या उनका निधन हुआ:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होगा और उपरोक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि जैसा भी मामला हो, विनियम 39 का उप-विनियम (1) या उक्त विनियम के खंड (ए) का उप-खंड (i) और उप-विनियम (3) के खंड (बी) का उप-खंड (i) प्रावधानों के अनुसार देय होगी";

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(vii) तेरह हजार दो सौ अस्सी केवल उन कर्मचारियों के संबंध में, अधिकारी और कामगार दोनों,

जो 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या उनका निधन हुआ:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होगा और उपरोक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी.

6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट-II में, खंड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, औद्योगिक श्रमिकों के लिए शृंखला 1960=100 अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2288 अंक से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों पर महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो. महंगाई राहत में उक्त प्रत्येक 4 अंक के लिए ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

बशर्ते कि 1 मई, 2005 को या उसके बाद से उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए लेकिन 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पहले, महंगाई राहत इस खंड के अनुसार देय होगी:

बशर्ते कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हों, औद्योगिक श्रमिकों के लिए शृंखला 1960=100 अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2836 अंक से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों पर महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो. महंगाई राहत में उक्त प्रत्येक 4 अंक के लिए ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

बशर्ते कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हों, औद्योगिक श्रमिकों के लिए शृंखला 1960=100 अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 4440 अंक से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों पर महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो. महंगाई राहत में उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हों, औद्योगिक श्रमिकों के लिए शृंखला 1960=100 अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 6352 अंक से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों पर महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो. महंगाई राहत में उक्त प्रत्येक 4 अंकों के लिए वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

7. उक्त विनियमों के परिशिष्ट III में, खंड (एफ) के बाद, निम्नलिखित खंड प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

‘(जी)’ 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में :

वेतनमान प्रति माह	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु.15,880 तक	वेतन का 30 फीसदी मूल पारिवारिक पेंशन होगा और अतिरिक्त 30 प्रतिशत भत्ते की राशि, जिसकी गणना भविष्य निधि में योगदान के लिए की जाती है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी : बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का योग न्यूनतम 3985 रुपये प्रति माह हो.
रु. 15,881 से रु 31,760 तक	वेतन का 20 फीसदी मूल पारिवारिक पेंशन होगा और अतिरिक्त 20 प्रतिशत भत्ते की राशि, जिसकी गणना भविष्य निधि में योगदान के लिए की जाती है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी : बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का योग न्यूनतम 4900 रुपये प्रति माह हो.
रु 31760 से ऊपर	वेतन का 15 फीसदी मूल पारिवारिक पेंशन होगा और अतिरिक्त 15 प्रतिशत भत्ते की राशि, जिसकी गणना भविष्य निधि में योगदान के लिए की जाती है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी : बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का योग न्यूनतम 6365 रुपये प्रति माह और अधिकतम रु 13280 होगी.

(एच) 1 अप्रैल, 2021 से खंड (ए) से (जी) प्रभावी नहीं होंगे और उक्त खंड में उल्लिखित सभी कर्मचारियों (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में, वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन और अतिरिक्त 30 प्रतिशत भत्ते की राशि, जिसकी गणना भविष्य निधि में योगदान के लिए की जाती है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी :

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन

जिन विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है, उनका इस संबंध में संबंधित बैंकों और बैंकों के शीर्ष स्तरीय कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित समझौतों और संयुक्त नोटों के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हैं. इसलिए, ऐसे भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

सी एम मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./438/2024-25]

**पाद टिप्पण:** मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या पेंशन 1, दिनांक 29 सितंबर, 1995 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या यूबीआई/एचआर/22300, दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से किए गए थे।

**UNION BANK OF INDIA**  
**(Human Resources Department)**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 28th August, 2024

**No. UBI:HR:16061 (E).**— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Union Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Union Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Union Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Union Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos shall be inserted, namely:—  
 “Provided further that special allowance introduced with effect from the 1st day of November, 2012 shall be excluded:  
 Provided also that an employee who was in the services of the Bank as on the 1st November, 2017 and whose stagnation increments have been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later.”.
3. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:—  
 “Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits.”.
4. In regulation 36 of the said regulations, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—  
 “(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of a part-time employee drawing 1/2 scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017.”.
5. In regulation 40 of the said regulations,—
  - (a) in sub-regulation (1), —
    - (i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—  
 “Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment.”;
    - (ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—  
 “(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private sector or self-employment, etc. exceeds rupees twelve thousand per month.”;
  - (b) in sub-regulation (4),—
    - (i) in clause (a), alter sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—  
 “(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1<sup>st</sup> day of April, 2021, sub-clauses (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.”;

(ii) in clause (b), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:-

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub regulation (1) of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of the said regulation, as the case may be.”;

(iii) in clause (c), after the sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely: —

“(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39.”.

6. In Appendix-II to the said Regulations, for clause (4), the following shall be substituted,namely:-

“(4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent. of basic pension.”.

7. In Appendix III to the said regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(g) in respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:

Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)
Up to Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.

Rs. 15,881 to Rs.31,760	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowance, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.
Above Rs. 31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month.

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent. of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension.”.

### Explanatory Memorandum

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

C M MINOCHA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./438/2024-25]

**Footnote:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 vide notification number PENSION 1, dated the 29th September, 1995 and lastly amended vide notification number UBI/HR/22300, dated the 4th October, 2023.